


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

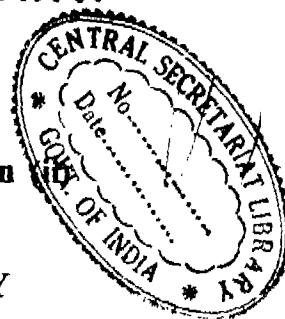
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-Section

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 165] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 17, 1979/चैत्र 27, 1901

No. 165] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 17, 1979/CHAITRA 27, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधि सूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1979

का. आ. 209 (अ).—केंद्रीय सरकार ने, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, अन्तर्देशीय व्यापार तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 711, तारीख 18 फरवरी, 1970 द्वारा, उपर्युक्त अधिसूचना में निर्विष्ट मामलों की जांच करने और उनके संबंध में रिपोर्ट देने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया था, जिसके एक मास सक्षम भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, श्री ए. के. सरकार थे, और

केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि आयोग का निरन्तर बना रहना अनावश्यक है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि यह आयोग 18 अप्रैल, 1979 से अस्तित्व में नहीं रह जाएगा ।

[फा. सं. 1/13/78-एस. सी. यूनिट]

पी. सी. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 1979

S.O. 209(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs No. S.O. 711 dated 18th February, 1970, the Central Government had appointed, under section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), a Commission of Inquiry consisting of Shri A. K. Sarkar, formerly Chief Justice of the Supreme Court of India, to enquire and report on and in respect of the matters referred to in the aforesaid notification; and

Whereas the Central Government is of the opinion that the continued existence of the Commission is unnecessary ;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (i) of section 7 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby declare that the Commission shall cease to exist with effect from 18th April, 1979.

[F. No. 1/13/78-S.C. Unit]

P. C. NAYAK, Jt. Secy.